जीवन हर समस्या का समाधान है कुछ मुश्किल है तो कुछ आसान है।

तेवर वही, अंदाज नया .....!
साप्ताहिक

उज्जैन टाइम्स

डाक रजिस्ट्रेशन नं. मालवा डिवीजन-
L2/65/RNP/397/2024-2026

प्रधान सम्पादक : मनमोहन शर्मा

RNI No. 7583/61

● वर्ष : 63, अंक : 42 ● उज्जैन, मंगलवार दिनांक 16-07-2024 से 22-07-2024 तक ● पृष्ठ : 08 ● मूल्य : 2 रुपये

SDG India Index & (इंडिया इंडेक्स) 2023-24 : 4th Index

सतत विकास लक्ष्यों (SDG) पर राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय प्रगति को मापने के लिए देश के प्रमुख उपकरण का yth Inde& (चौथा संस्कर) नीति आयोग द्वारा जारी किया गया।

SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (NIF) से जुड़े 113 संकेतकों पर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की राष्ट्रीय प्रगति को मापता है और ट्रैक करता है।

सतत विकास पर 2030 एजेंडा को अपनाने के बाद से एसडीजी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता नीति आयोग के नेतृत्व में एसडीजी स्थानीयकरण पर ठोस प्रयासों में परिलक्षित होती है, जो राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ मिलकर काम करता है।

2018 में एसडीजी इंडिया इंडेक्स के लॉन्च ने स्थानीयकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणा प्रदान की, इस परिवर्तनकारी यात्रा में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को प्रमुख हितधारकों के रूप में फिर से पुष्टि की।

SDG (एसडीजी) India Inde& इंडिया इंडेक्स के चौथे संस्करण की मुख्य विशेषताएं और परिणाम-

भारत का समग्र स्कोर 2018 में 57 से बढ़कर 2020-21 में 66 हो गया और 2023-24 में 71 हो गया।

लक्ष्य 1 (गरीबी नहीं), 8 (सभ्य कार्य और आर्थिक विकास), 13 (जलवायु कार्रवाई) में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है। ये अब फ्रंट रनर श्रेणी (65-99 के बीच का स्कोर) में हैं।

इनमें से, लक्ष्य 13 (जलवायु कार्रवाई) ने सबसे अधिक सुधार दिखाया है, इसका स्कोर 54 से बढ़कर 67 हो गया है। लक्ष्य 1 (कोई गरीबी नहीं) इसके करीब है, इसका स्कोर 60 से बढ़कर 72 हो गया है। प्रगति प्रभावों को रेखांकित करती है नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के केंद्रित कार्यक्रम संबंधी हस्तक्षेप और योजनाएं।

2018 के बाद से, भारत ने कई प्रमुख एसडीजी में पर्याप्त प्रगति देखी है। लक्ष्य 1 (गरीबी नहीं), 3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण), 6 (स्वच्छ

जल और स्वच्छता), 7 (सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा), 9 (उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा) और 11 (सतत शहर और समुदाय)।

एसडीजी उपलब्धियों को सुविधाजनक बनाने वाले प्रमुख हस्तक्षेपों में शामिल हैं-

● पीएम आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत 4 करोड़ से अधिक घर।

● ग्रामीण क्षेत्रों में 11 करोड़ शौचालय और 2.23 लाख सामुदायिक स्वच्छता परिसर।

● पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन।

● जल जीवन मिशन के तहत 14.9 करोड़ से अधिक घरों में नल जल कनेक्शन।

● आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 30 करोड़ से अधिक लाभार्थी।

● राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों का कवरेज।

● 150,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों तक पहुंच जो प्राथमिक चिकित्सा देखभाल प्रदान करते हैं और सस्ती जेनेरिक दवाएं प्रदान करते हैं।

● पीएम-जन धन खातों के माध्यम से 34 लाख करोड़ का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी)।

● स्किल इंडिया मिशन के कारण 1.4 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित और कुशल बनाया गया है और 54 लाख युवाओं को फिर से कुशल बनाया गया है।

● पीएम मुद्रा योजना ने फंड ऑफ फंड्स के अलावा युवाओं की उद्यमशीलता की आकांक्षाओं के लिए कुल मिलाकर ?22.5 लाख करोड़ के 43 करोड़ ऋण स्वीकृत किए।

● स्टार्ट अप इंडिया और स्टार्ट अप गारंटी योजनाएं युवाओं की सहायता कर रही हैं।

● बिजली तक पहुंच के लिए सौभाग्य योजना।

● नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर देने के परिणामस्वरूप पिछले दशक में सौर ऊर्जा क्षमता 2.82 गीगावॉट से बढ़कर 73.32 गीगावॉट हो गई।

● 2017 और 2023 के बीच, भारत ने लगभग 100 गीगावॉट स्थापित विद्युत क्षमता जोड़ी है, जिसमें से लगभग 80 प्रति. गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित संसाधन के लिए जिम्मेदार है।

● इंटरनेट डेटा लागत में 97% की कमी के साथ डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार, जिसने वित्तीय समावेशन को सकारात्मक रूप से प्रभावित और बढ़ावा दिया है।

एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 एक ऑनलाइन डैशबोर्ड पर भी लाइव है। डैशबोर्ड राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तरों पर महत्वपूर्ण विकास परिणाम आधारित अंतरालों की पहचान करने के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल विजुअलाइजेशन प्रदान करता है।

नीति आयोग एसडीजी के स्थानीयकरण और त्वरण में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो कि विकसित भारत @2047 की दिशा में प्रगति को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण बैरोमीटर है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स हमारी प्रगति को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

शिक्षा के क्षेत्र में एक जाना माना नाम
महर्षि सांदीपनि पब्लिक हाई स्कूल

महर्षि सांदीपनि पब्लिक हाई स्कूल विगत 24 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। उज्जैन शहर में 13 बच्चों की संख्या से प्रारंभ विद्यालय आज 1500 बच्चों का सुखद भविष्य गढने हेतु प्रयत्नरत है। विद्यालय अपनी प्री प्रायमरी नर्सरी व के.जी. की कक्षाओं में नवाचार के लिए प्रसिद्ध है। अपने पाल्य के प्रवेश हेतु निवेदन है कि एक बार अवश्य विद्यालय का अवलोकन करे।

प्राचार्य
● भारती महेश तिवारी

सम्पादकीय

लोकतंत्र में हिंसा का क्या काम?

रिपब्लिकन पार्टी के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि जो बाइडेन के भाषणों से ट्रंप पर हमला करने की शह मिली। यह हत्या का प्रयास था। हालांकि अमेरिका में यह पहली घटना नहीं है, जब किसी नेता पर जानलेवा हमला हुआ। मगर दुनिया भर में सबसे सतर्क और चाक-चौबंद मानी जाने वाली अमेरिकी सुरक्षा प्रणाली पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि ट्रंप पर हमला करने वाले के बारे में घटना से कुछ समय पहले सूचना दे दी गई थी। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया है कि हमलावर को पास के घर की छत पर स्पष्ट रूप से देखा गया था और उसने सुरक्षाकर्मियों को इसकी सूचना भी दी थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के बाद स्वाभाविक ही वहां की सुरक्षा और खुफिया एजंसियों पर सवाल उठने लगे हैं। ट्रंप इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में फिर से उम्मीदवार हैं। वे पेन्सिल्वेनिया के बटलर में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे कि एक युवक ने पास की एक छत से उन पर गोली दाग दी। गनीमत है कि निशाना चूक गया और गोली ट्रंप के दाहिने कान को चीरती हुई निकल गई। सुरक्षाकर्मियों ने हमलावर को वहीं ढेर कर दिया। राष्ट्रपति जो बाइडन ने घटना की सख्त निंदा की है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। मगर इस घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। चूंकि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मी है और ट्रंप की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है, इस घटना को राजनीति के केंद्र में ला दिया गया है। कई विश्लेषक मानते हैं कि इस घटना से ट्रंप को सहानुभूति मिलेगी और उनकी दावेदारी और मजबूत होगी। हालांकि अमेरिका में मतदाताओं को इस तरह प्रभावित करना थोड़ा कठिन माना जाता है। अमेरिकी खुफिया एजंसी एफबीआइ अभी पता नहीं लगा सकी है कि हमलावर का उद्देश्य क्या था। उसका कहना है कि हमलावर ने अकेले हमले की योजना बनाई थी, उसका किसी अन्य समूह से कोई संबंध नहीं था, इसलिए उसके मकसद के बारे में जान पाना कठिन है। मगर अमेरिका में पिछले कुछ समय से जिस तरह का वातावरण बना है, उसमें युवाओं के भीतर पनपे हिंसक व्यवहार का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। पिछले चुनाव में जब ट्रंप चुनाव हारे थे, तब उनके समर्थक अमेरिकी संसद में घुस गए और वहां भारी तोड़-फोड़ की थी। वहां नस्लीय हिंसा और दूसरे देशों के नागरिकों के प्रति युवाओं में नफरत का जैसा मानस बना है, उससे वहां के वातावरण का अंदाजा लगाया जा सकता है। छिपी बात नहीं है कि अमेरिका में महंगाई और बेरोजगारी के कारण बहुत सारे युवाओं में नाराजगी है।

पाकिस्तान की बर्बादी का कारण चीन बनेगा

पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकवादी हरकतों को अंजाम देता रहा है। मुंबई में 2008 में हुए हमलों से लेकर कठुआ, पठानकोट और उरी वगैरह में उसने आतंक फैलाया है। पर अब पाकिस्तान खुद ही अपने द्वारा लगाये आतंकवाद की आग में स्वाहा हो रहा है। वह भयभीत है।

डर का कारण चीन का नाराज होना है। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों के मारे जाने के कारण चीन सरकार उससे सख्त नाराज है। इसलिए सारे पाकिस्तान में चीनी नागरिकों को अब खास सुरक्षा दी जा रही है, जो पाकिस्तान में चीन की मदद से चल रही परियोजनाओं में काम कर रहे हैं। चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए इस्लामाबाद में एक नया पुलिस बल भी बनाया गया है। ये सब इसलिए हो रहा है, क्योंकि चीनी वित्त पोषित मेगा परियोजनाओं को निशाना बनाया जा रहा है। इनमें काम करने वाले चीनियों को आतंकवादी चुन-चुन कर मार रहे हैं। इन हमलों के कारण ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाएं खतरे में हैं।

चीन ने पाकिस्तान में अपना बड़े स्तर पर निवेश करना 2015 शुरू किया था। चीन की योजना थी कि वह पाकिस्तान में 60 अरब डॉलर का निवेश विभिन्न परियोजनाओं में करे। इस वक्त हजारों चीनी कामगार और इंजीनियर पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में युद्ध समाप्त होने के बाद अमेरिका से मदद मिलनी बंद हो गई थी। उसके बाद, उसे चीनी निवेश का ही एक मात्र सहारा था। उस पर भी फिलहाल तो ग्रहण लग गया दिखता है।

पिछले तीन वर्षों में, पाकिस्तान में आतंकवादी समूह फिर से उभरे हैं। इस दौरान आतंकवादी हमलों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसका असर चीनी परियोजनाओं पर खूब ज्यादा हुआ है।

इस कारण से चीन से पोषित परियोजनाओं पर काम ठंडा पड़ने लगा है। पिछले मार्च के महीने के अंत में, सशस्त्र आतंकियों ने अरब सागर के दक्षिण-पश्चिमी तट पर स्थित ग्वादर में चीनी निर्मित और संचालित बंदरगाह को निशाना बनाया, जिसमें दो पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों की मौत हो गई। कुछ दिनों बाद, आतंकवादियों ने देश के दूसरे सबसे बड़े एयर बेसपर हमला किया। यह बलूचिस्तान में है। यहाँ भी चीनी नागरिक सक्रिय थे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी।

पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हमले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कुछ समय पहले पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक जलविद्युत परियोजना पर आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें पांच चीनियों की मौत हो गई। इसके बाद चीनी कंपनियों ने कम से कम तीन महत्वपूर्ण जलविद्युत परियोजनाओं पर अपना काम रोक दिया था। ये परियोजनाए थीं- दासू बांध, डायमर-बाशा बांध और तारबेला पांचवां एक्सटेंशन। खैबर पख्तूनख्वा सीमांत गांधी के प्रभाव वाला क्षेत्र रहा है। चीनियों पर हमले खैबर पख्तूनख्वा के अलावा बलूचिस्तान में भी हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सटे हुए अफगानिस्तान से।

पाकिस्तान के मशहूर अखबार दि डॉन में 1 अप्रैल, 2024 को छपी एक खबर के अनुसार, इस साल के पहले तीन महीनों में देश के दो प्रमुख राज्यों क्रमशः खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बीते साल की इसी अवधि की तुलना में आतंकी और हिंसक वारदातों में 92 और 86 फीसद बढ़ोतरी हुई है।

जाहिर है, अपने नागरिकों पर हमले के कारण चीन नाराज है। पाकिस्तान चीन को अपना सबसे भरोसे का मित्र कहता है। चीन के नाराज होने से पाकिस्तान की सांसें रूक रही हैं। पाकिस्तान से मिल रही खबरों पर यकीन करें तो कुछ चीनी नागरिक अपनी जान को खतरा होने के कारण पाकिस्तान छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार बार-बार अपराधियों को पकड़ने का वादा कर रही है। लेकिन, हो कुछ नहीं रहा है। चीनियों पर हो रहे हमलों के लिए तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी), बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और इस्लामिक स्टेट-खुरासान को जिम्मेदार माना जा रहा है। ये तीनों इस्लामिक आतंकी संगठन अब पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लगभग जंग छेड़े हुए हैं।

खैबर पख्तूनख्वा के हजारा और कोहिस्तान इलाकों को बहुत बीहड़ माना जाता है। ये क्षेत्र हत्याओं, लड़कियों के स्कूलों को जलाने और शिया मुसलमानों की हत्याओं के कारण कुख्यात रहे हैं। अब ये चीनी नागरिकों को मारने के कारण भी खबरों में रहने लगे हैं। खैबर में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। इधर सरकार का डर या इकबाल खत्म हो चुका है। यहां पुलिस, सरकारी अफसर या राजनीतिक नेतृत्व आतंकियों के सामने आत्मसमर्पण कर चुके हैं। इस बात की संभावना न के बराबर है कि इधर चीनियों पर हमले थमेंगे। खैबर पख्तूनख्वा अंधकार युग में जा चुका है। सवाल यह है कि चीनी नागरिकों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? देखा जाए तो यह वहां पर वे विकास परियोजनाओं को खड़ा कर रहे हैं। दरअसल बलूचिस्तान और खैबर के लोगों का कहना है कि उनके यहां लगने वाली परियोजनाओं का स्थानीय जनता को लाभ नहीं मिलता।

सारी मलाई पंजाब का खा जाता है। इसका विरोध करने के लिए ही चीनियों पर हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान की सेना और सरकार का मतलब पंजाब ही है।

बलूचिस्तान में पंजाबी विरोधी आंदोलन से पाकिस्तान सरकार की नींद बुरी तरह उड़ी हुई है। उसका इस बलूचों के आंदोलन के कारण परेशान होना समझ भी आता है। इधर ही चीन की मदद से 790 किलोमीटर लंबा ग्वादर पोर्ट बन रहा है। पाकिस्तान को लगता है कि ग्वादर पोर्ट के बन जाने से देश की तकदीर बदल जाएगी। पर बलूचिस्तान के अवाम को यह नहीं लगता है। उसका मानना है कि ग्वादर पोर्ट बनने से सिर्फ पंजाब के हितों को ही लाभ होगा। बलूचिस्तान की जनता को लगता है कि उनके क्षेत्र के संसाधनों से पंजाब और पंजाबियों का ही पेट भरा जाएगा। इसलिए ही बलूचिस्तान में पंजाबियों से घोर नफरत की जाती है। बलूचिस्तान पाकिस्तान से शुरू से ही अलग होना चाहता है।

वह 1947 में ही भारत का अंग बनना चाहता था जिसे नेहरू जी ने जबर्दस्ती पाकिस्तान की झोली में डाल दिया था। पाकिस्तान सेना की ताकत ने ही उसे पाकिस्तान का हिस्सा बनाकर रखा हुआ है। पिछले महीने, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, शहबाज शरीफ, बीजिंग गए थे। वे चीन के शिखर नेता शी जिनपिंग से मिले। लेकिन, इस यात्रा का कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला। क्योंकि चीन से पाकिस्तान में निवेश करने को लेकर कोई वादा नहीं किया। चीन ने पाकिस्तान में चीनियों पर हमलों पर नाराजगी जताई। यकीन मानिए कि अगर चीन ने पाकिस्तान के कटोरे में भीख डालना बंद कर दिया तो पाकिस्तान तो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा।

कोटक सिक्योरिटीज के अनुसार, एनएसई निफ्टी 500 में शामिल 37 कंपनियों के प्रमोटरों ने इस साल जून तक लगभग 87,400 करोड़ रुपये बेचे हैं-जो पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक है और ऐसा व्यापार विस्तार, न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों के अनुपालन, ऋण में कमी और प्रमोटर हितों के रणनीतिक पुनर्गठन के कारण हुआ है।

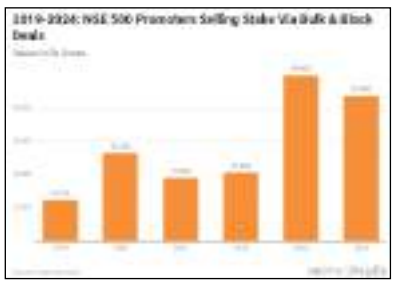

PRESS INFORMATION BUREAU
GOVERNMENT OF INDIA
PRESS NOTE
RESULT OF THE CIVIL SERVICES (PRELIMINARY) EXAMINATION, 2024

Dated: 1st July, 2024

On the basis of the result of the Civil Services (Preliminary) Examination, 2024 held on 16/06/2024, the candidates with the following Roll Numbers have qualified for admission to the Civil Services (Main) Examination, 2024.

The candidature of these candidates is provisional. In accordance with the Rules of the Examination, all these candidates have to apply again in the Detailed Application Form-I (DAF-I) for the Civil Services (Main) Examination, 2024. The dates and important instructions for filling up of the DAF-I and its submission will be announced in due course on the website of the Commission.

Candidates are also informed that marks, cut off marks and answer keys of CS (P) Examination, 2024 will be uploaded on the Commission's website i.e. https://upsc.gov.in only after the entire process of the Civil Services Examination, 2024 and Indian Forest Service Examination, 2024 is over i.e. after the declaration of final result.

The Union Public Service Commission has a Facilitation Counter near the Examination Hall Building in its premises at Dholpur House, Shahjahan Road, New Delhi. Candidates may obtain any information/clarification regarding their result of the above mentioned Examination on all working days between 10.00 AM to 5.00 PM, in person or on Tel. No. 011-23385271, 011-23098543 or 011-23381125 from the Facilitation Counter.

यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2024 के नतीजे घोषित। भाग्यशाली चयनित उम्मीदवारों को बधाई!

भारत की ग्रैंड रणनीति

ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के उपाध्यक्ष गौतम चिकरमाने ने एक मोनोग्राफ लिखा है, जिसमें एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है और तर्क दिया गया है कि अब समय आ गया है कि पीएमओइंडिया और भारत सरकार, भारत की भव्य रणनीति को स्पष्ट करें और उसे क्रियान्वित करें।

McKinsey-कार्यप्रणाली संदेह में

जब प्रबंधन परामर्श फर्म मैकिंसे ने 2015 में घोषणा की कि उसे मुनाफे और कार्यकारी नस्लीय और लैंगिक विविधता के बीच संबंध मिला है, तो यह एक बड़ी सफलता थी। इस शोध का उपयोग निवेशकों, लॉबिस्टों और विनियामकों द्वारा बोर्ड में अधिक महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों को शामिल करने और उन्हें नियुक्त करने वाली कंपनियों में निवेश को उचित ठहराने के लिए किया गया था। 2015 से, इस दृष्टिकोण का बाजार में परीक्षण किया गया और यह विफल रहा। शिक्षाविदों ने McKinsey के निष्कर्षों को दोहराने की कोशिश की और विफल रहे, यह निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में लाभप्रदता और कार्यकारी विविधता के बीच कोई संबंध नहीं है। और McKinsey के शुरुआती अध्ययनों की कार्यप्रणाली, जिसने व्यापक विश्वास बनाने में मदद की कि विविधता मुनाफे के लिए अच्छी है, पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

नदी जोड़ो परियोजना

मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकारों ने रविवार को 72,000 करोड़ रुपये की पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ो परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस लिंक परियोजना का उद्देश्य पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों, मध्य प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्रों में पेयजल और औद्योगिक जल उपलब्ध कराना है।

इसके अलावा दोनों राज्यों में न्यूनतम 2.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध कराना है। इसमें राज्यों में रूट टैंकों का पूरकीकरण भी शामिल है। उज्जैन को सबसे ज्यादा फायदा।

खतरे का संकेत @ USA

जर्मनी, इटली, रोमानिया और बुल्गारिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर खतरे का स्तर बढ़ाकर चार्ली कर दिया गया है, जिसका मतलब है आतंकवाद का आसन्न खतरा यह कम से कम दस वर्षों में सबसे अधिक खतरा स्तर है। जानिए चार्ली के आलावा और क्या कोड वर्ड है।

मानसून

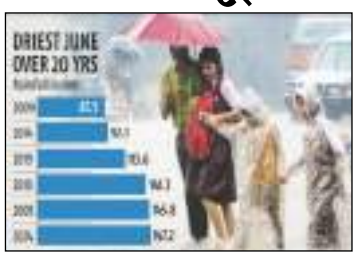

जून में असमान रूप से चलने के बाद, दक्षिण-पश्चिम मानसून के जुलाई में जोरदार होने की उम्मीद है, पूरे देश में अखिल भारतीय औसत बारिश लंबी अवधि के औसत का 106 प्रति. होने का अनुमान है, जो सामान्य से ऊपर है।

सबसे गर्म महीना

जून 24-सबसे गर्म महीना 100 सालों में देश में 100 साल में पहली बार जून सबसे गर्म, सामान्य से कम हुई बारिश जुलाई में IMD ने बताया कि सामान्य रहेगा मानसून।

एशियाई कुश्ती-अंडर 19

अंडर 23 एशियाई में भारत शीर्ष पर रहा। युवा भारतीय पहलवानों ने फ्रीस्टाइल कुश्ती में कुल 8 पदक जीते।

बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने स्टॉक एक्सचेंजों, स्टॉक ब्रोकरों, क्लियरिंग कॉरपोरेशनों और डिपॉजिटरीज सहित बाजार अवसंरचना संस्थानों (MII) से कहा है कि वे 1 अक्टूबर से सभी सदस्यों के लिए उनकी मात्रा या गतिविधि के आधार पर शुल्क लगाने के बजाय एक समान और बराबर शुल्क संरचना लागू करें।

सेबी ने हाल ही में निवेशकों के लिए एक परीक्षा शुरू की है। यह अब तक एक स्वैच्छिक परीक्षा है। सिंगापुर में डीमैट खाता खोलने और म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान में निवेश करने से पहले इस प्रकार की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होता है।

टोक्यो का निक्केई 225 इतिहास में पहली बार 42,000 के स्तर को पार कर गया। इस सूचकांक को नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने में 35 साल लग गए।

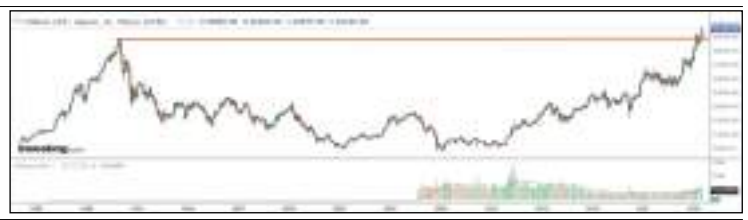

भारत का इक्विटी एयूएम जून 24 में 30 ट्रिलियन रुपये को पार कर गया, जो पिछले 4 वर्षों में 4 गुना से अधिक है।

सेंसेक्स ने रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ, पहली बार 80,000 के पार पहुंचा

इस बेंचमार्क इंडेक्स ने अब तक की सबसे तेज 10,000 अंकों की बढ़त दर्ज की है (इसे 70,000 से 80,000 तक पहुंचने में 6 महीने लगे हैं)।

75 प्रतिशत मिट्टी पहले ही क्षरित हो चुकी है

75 प्रतिशत मिट्टी पहले ही क्षरित हो चुकी है, जिसका सीधा असर 3.2 बिलियन लोगों पर पड़ रहा है। अगर यही स्थिति रही, तो

मौजूदा रुझान के अनुसार 2050 तक इसका असर 90 प्रति. तक हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने एक सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा कि 2050 तक धरती की सतह का 90 प्रतिशत हिस्सा क्षरित हो सकता है। यह भयावह भविष्यवाणी वैश्विक जैव विविधता और मानव जीवन के लिए एक बड़े खतरे को उजागर करती है।

वैश्विक भूख पर प्रगति उलट गई है

वैश्विक भूख पर प्रगति उलट गई है। 2 जुलाई, 2024 को जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया की लगभग 30 प्रतिशत आबादी खाद्य असुरक्षा का सामना कर रही है और 42 प्रतिशत लोग स्वस्थ आहार का खर्च उठाने में असमर्थ हैं।

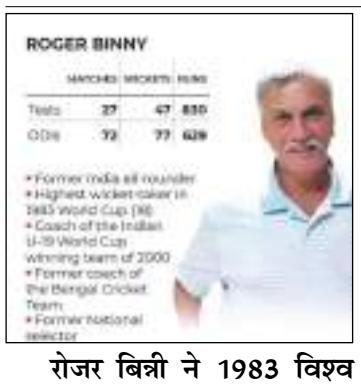

रोजर बिन्नी ने 1983 विश्व कप जीता खिलाड़ी के रूप में 2000 अंडर-19 विश्व कप जीता, कोच के रूप में 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीता चयनकर्ता के रूप में 2024 टी20 विश्व कप जीता।

भारत चैंपियन

भारतीय पहलवान विनेश फोगट ने स्पेन में मैड्रिड ग्रैंड प्रिक्स में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को गौरवान्वित किया।

fssai
Food Safety and Standards Authority of India

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लेबल पर मोटे अक्षरों और बढ़े हुए फॉन्ट आकार में कुल चीनी, नमक और संतृप्त वसा के बारे में पोषण संबंधी जानकारी प्रदर्शित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

पोषण संबंधी जानकारी लेबलिंग के संबंध में खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 में संशोधन को मंजूरी देने का निर्णय खाद्य प्राधिकरण की 44वीं बैठक में लिया गया।

बांध रही बंदनवार

जन्मों से बांध रही बंदनवार,
कब आओगे प्रभु,
तुम मोरे द्वार।
वंचित तेरे दर्शन को क्यों
मेरा हर त्यौहार,
क्यों नहीं आते बताओ प्रभु
तुम मेरे द्वार।
भक्ति के अलावा दे ना पाई
तुम्हें कोई उपहार,
क्या इसलिए नहीं आते तुम
मेरे द्वार छोड़ी देहरी बिरला
दिया मैंने घर बार।
फिर भी नहीं आए,
प्रभु तुम मेरे द्वार।
त्यागा हृदय से कर्मों का हर
व्यापार, काश! प्रभु तुम
आजाते एक बार मेरे द्वार।
बांह तुम थाम लो मेरी डूबत
हूं मंझधार, शीघ्र आओ प्रभु
देर न करो इस बार।
आस दर्शन की कर दो पूरी
सुन रहे ना करतार, ठुकराओ
ना मुझे कर लो,
मुझे स्वीकार।
आशाओं से चौक ही पूरा
विश्वास का द्वाराचार,
विनती करती हूं तुमसे,
आजो प्रभु मोरे द्वार।
हृदय स्पंदन हो रहा मौन टूट
रहा सांसों का तार,
स्नेह दीप बुझने से पहले,
प्रभु मेरे संग बांधो बंदनवार।

● पूर्णिमा जोशी
'पूनमसरल'

Deputy NSA

IPS TV रविचंद्रन भारत के नये डिप्टी NSA बनाये गये,जो अभी IB में स्पेशल डायरेक्टर हैं। पूर्व रॉ चीफ राजिंदर खन्ना अतिरिक्त NSA बने।

योग @ एशियन गेम्स

योग को 2026 में जापान के नागोया में आयोजित होने वाले एशियाई खेलों में एक प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया जाएगा, जिसमें कोई पदक नहीं दिया जाएगा। इसे 2030 में दोहा एशियाड में पदक दौर के साथ एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में शामिल किया जाएगा।

Day Working @ Greece

6 दिन का कार्य सप्ताह शुरू करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश यूरोप में आर्थिक रूप से हालात इतने खराब हैं कि वे 6 दिन का कार्य सप्ताह शुरू कर रहे हैं और ग्रीस जैसे कुछ देश भी ऐसा ही कर रहे हैं।

सेंसेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर

सेंसेक्स ने रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ, पहली बार 80,000 के पार पहुंचा। इस बेंचमार्क इंडेक्स ने अब तक की सबसे तेज 10,000 अंकों की बढ़त दर्ज की है (इसे 70,000 से 80,000 तक पहुंचने में 6 महीने लगे हैं)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के एक स्वायत्त संस्थान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उन्नत अध्ययन संस्थान (आईएएसएसटी) ने कार्बनिक प्रदूषकों के फोटोकैटेलिटिक क्षरण के लिए एक अभिनव धातु ऑक्साइड नैनोकंपोजिट विकसित किया है। यह काम हाल ही में एल्सेवियर (इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कम्युनिकेशंस) पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तैयार किए गए नैनोकंपोजिट में कटैलिसीस, ऊर्जा भंडारण, सेंसर, ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स, बायोमेडिकल क्षेत्रों, कोटिंग्स और जल विभाजन के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में संभावित अनुप्रयोग हो सकते हैं।

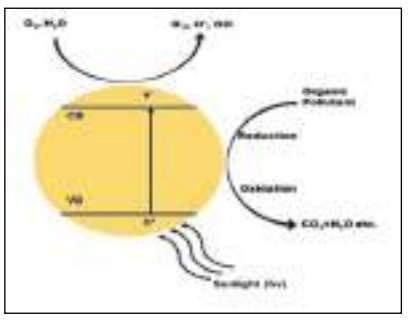

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का होगा विस्तार-मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को देश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के साथ ही मध्यप्रदेश स्थित प्रमुख धार्मिक स्थलों के भ्रमण करवाये जाने को दृष्टिगत रखते हुए योजना का विस्तार किया जाए। इसके लिए धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग आवश्यक अध्ययन कर कार्य-योजना तैयार करे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के स्थानों की यात्रा से जहां बुजुर्ग यात्रियों को अपने ही प्रदेश के प्रसिद्ध स्थान देखने और देव दर्शन का अवसर मिलेगा वहीं प्रदेश की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण होगा। प्रदेश की भौगोलिक रचना के कारण नागरिक अनेक तीर्थ स्थान देख नहीं पाते और अपने ही प्रदेश की विशेषताओं से अनजान रहते हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के क्रियान्वयन संबंधी मंत्रालय में हुई बैठक में कहा कि युवा वर्ग को भी प्रदेश की पुरा-संपदा और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों से परिचित करवाने के लिए अन्य विभाग भी पहल करें। ज्ञान-विज्ञान के केंद्रों, ऐतिहासिक महत्व के स्थानों, प्राकृतिक सुंदरता के स्थानों और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों तक युवाओं को ले जाने से उनके ज्ञान में वृद्धि होगी। जनजातीय विकास विभाग द्वारा प्रत्येक जिले से मेरिट एवं अन्य आधार पर विद्यार्थियों का चयन कर उन्हें प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थानों का भ्रमण करवाया जाए। धार्मिक न्यास,धर्मस्व मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री संजय कुमार शुक्ला एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में अनेक लोक गायक, संगीतकार और कलाकार निवास करते हैं। इन्हें प्रदेश के विभिन्न स्थानों के भ्रमण के लिए आमंत्रित किया जाए। वे मंचीय प्रस्तुति के लिये अपनी यात्रा, पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ करें। विभिन्न देव स्थानों के भ्रमण का लाभ भी उन्हें मिलेगा। ऐसे स्थानों पर आने वाले देश- विदेश के पर्यटकों और श्रद्धालुओं तक कलाकारो की कला भी पहुंचेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थानों के साथ ही अन्य देव स्थलों पर भी विभिन्न सुविधाओं का विकास आवश्यक है। देव स्थल परिसर सुविधायुक्त हों, इसके लिए विभिन्न संबंधित विभाग सक्रिय रहें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राम राजा की नगरी ओरछा, शारदा माता के स्थान मैहर, बड़ा महादेव मंदिर, चौरागढ़ महादेव, जटा शंकर पचमढ़ी पर व्यवस्थाएं बेहतर करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक लोकों के निर्माण के संबंध में अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की।

धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग द्वारा बैठक में प्रजेंटेशन में बताया गया कि प्रदेश में वर्ष 2012 से प्रारंभ मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का आईआरसीटीसी द्वारा योजना का संचालन किया जा रहा है। इसमें देश के 41 एकल तीर्थ स्थल और 9 युग्म तीर्थ स्थल सम्मिलित हैं। गत 12 वर्ष में प्रदेश के लगभग 8 लाख श्रद्धालुओं को योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। यात्रा के लिए 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों का चयन किया जाता है। महिलाओं के लिए दो वर्ष की छूट है। जो नागरिक 65 वर्ष से अधिक आयु के हैं अथवा दिव्यांग हैं उन्हें अपने साथ सहायक ले जाने की पात्रता है। तीर्थ यात्रियों को भोजन, रहने की सुविधा के साथ ही चिकित्सा, सुरक्षा और सड़क परिवहन सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है। विगत वित्त वर्ष में 29 भारत गौरव ट्रेनों के संचालन से प्रदेश के 18 हजार 480 श्रद्धालु लाभान्वित हुए। वर्तमान वित्त वर्ष में वाराणसी- अयोध्या, रामेश्वरम, द्वारका, जगननाथपुरी, कामाख्या, शिर्डी, हरिद्वार, मथुरा- वृंदावन, बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की दीक्षा भूमि (नागपुर) और स्वर्ण मंदिर अमृतसर के लिए 35 ट्रेनों की व्यवस्था कराई जाएगी। वर्ष 2023-24 से वायुयान द्वारा तीर्थ यात्रा भी शुरू की गई है। इसका लाभ प्रदेश के 25 जिलों के 790 तीर्थ यात्रियों को प्राप्त हुआ है। इन्हें भोपाल और इंदौर एयरपोर्ट से प्रयागराज, गंगासागर, शिर्डी और मथुरा वृंदावन की यात्राएं कराई गईं।

अडानी-हिंडनबर्ग विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका की खारिज

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने अडानी समूह द्वारा स्टॉक मूल्यों में कथित गड़बड़ी के आरोपों की जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) या केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने से इनकार करने संबंधी तीन जनवरी 2024 के अपने फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने अपने पिछले फैसले पर पुनर्विचार के लिए अनामिका जायसवाल द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दी। पीठ ने आठ मई को पारित अपने संक्षिप्त आदेश में कहा, समीक्षा याचिका का अवलोकन करने के बाद, रिकॉर्ड में कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है। शीर्ष अदालत के नियम 2013 के आदेश XLVII नियम 1 के तहत समीक्षा का कोई मामला नहीं बनता है। इसलिए, पुनर्विचार याचिका खारिज की जाती है। उच्चतम न्यायालय के नियमों के अनुसार, बिना संबंधित वकील से कागजात साझा किए न्यायाधीशों के कक्षों में पुनर्विचार याचिका पर विचार किया जाता है।

भारतीय सिविल सेवा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है

एक अभूतपूर्व निर्णय में, वित्त मंत्रालय ने भारतीय राजस्व सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा आधिकारिक तौर पर अपना नाम और लिंग बदलने की अपील को मंजूरी दे दी है-भारतीय सिविल सेवा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। आदेश के अनुसार, सुश्री एम अनुसूया, आईआरएस (सी एंड आईटी-2013) ने मंत्रालय को एक याचिका प्रस्तुत की, जिसमें उनका नाम बदलकर श्री एम अनुकथिर सूर्या करने और उनका लिंग महिला से पुरुष करने की सरकार की मंजूरी का अनुरोध किया गया। एम अनुसूया, आईआरएस (सी एंड आईटी-2013), वर्तमान में मुख्य आयुक्त (एआर), सीईएसटीएटी, हैदराबाद में संयुक्त आयुक्त के रूप में तैनात हैं।

वित्तीय प्रभावशाली व्यक्ति जो अपने ट्वीट/पोस्ट में स्टॉक का नाम बताते हैं, वे मुश्किल में पड़ जाएंगे। टि्वटर/फेसबुक/instagram/ Telegram / watsapp पर आनी वाली हर टिप से सावधान।

संसद बजट सत्र

संसद का बजट सत्र इस महीने की 22 तारीख से शुरू होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। उन्होंने बताया कि 2024-25 का केंद्रीय बजट 23 जुलाई को लोकसभा में पेश किया जाएगा।

बीसीसीआई द्वारा भारतीय टीम के लिए पुरस्कार राशि का बंटवारा

- सभी 15 खिलाड़ियों और द्रविड़ को 5-5 करोड़ मिलेंगे
- बाकी कोचिंग ग्रुप को 2.5-2.5 करोड़ मिलेंगे
- बैकरूम स्टाफ को 2-2 करोड़ मिलेंगे
- चयन समिति को 1-1 करोड़
- रिजर्व खिलाड़ियों को 1-1 करोड़।

न्याय वितरण प्रणाली का नया अध्याय-पिछले 75 वर्षों का सबसे बड़ा ऐतिहासिक सुधार

न्याय वितरण प्रणाली से संबंधित तीन नए कानून, आज दिनांक 21 दिसम्बर 2023 को संसद द्वारा पारित किए गए हैं। यह प्राचीन औपनिवेशिक कानूनों का स्थान लेता है। केंद्र सरकार ने भारत में न्याय वितरण प्रणाली का नया अध्याय खोला है। 25 दिसंबर 2023 को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीन आपराधिक विधेयकों- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 को मंजूरी दे दी। संसद के बाहर इसके आलोचक पहले ही इस बारे में जोर-शोर से बोल चुके हैं. इसके कुछ खंडों पर विपक्ष को कड़ी आपत्ति है।

ये नए कानून हर भारतीय को प्रभावित करेंगे और ये भारतीयों के लिए अनुच्छेद 370 या 2014 के बाद से पारित किसी भी अन्य कानून से अधिक महत्वपूर्ण हैं। हमारे पुलिस स्टेशन और अदालतें फिर कभी एक जैसी नहीं होंगी। इसका वास्तविक प्रभाव और इसकी विसंगतियाँ और कमजोरियाँ तब सामने आएंगी जब यह हमारे पुलिस स्टेशनों और हमारी निचली अदालतों में व्यवहार में आएगा।यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब इतने महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए और उन पर बहस हुई तो विपक्षी दलों के सदस्यों को निलंबित कर दिया गया।

पिछले 75 वर्षों में न्याय वितरण प्रणाली में सबसे बड़े ऐतिहासिक सुधार लाने के लिए गृह मंत्री को हमेशा टैग किया जाएगा। केवल समय ही बताएगा कि यह आम पुरुषों और महिलाओं को न्याय पाने में कैसे मदद करेगा। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के लिए ऐतिहासिक दिन, जो विरासत बनाते हुए सत्ता पर अपनी पकड़ दिखाती है। अमित शाह के अनुसार, पेश किए गए तीन नए आपराधिक कानून बिलों में तैयारी के चार पहलू शामिल हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार, 18 राज्यों, 6 केंद्र शासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, 16 उच्च न्यायालयों, 142 सांसदों, 270 विधायकों और आम जनता से फीडबैक प्राप्त हुआ।

भारतीय न्याय संहिता (भारतीय दंड संहिता, 1860 की जगह) नए बिल/कानून की मुख्य बातें

भारतीय न्याय संहिता आईपीसी के अधिकांश अपराधों को बरकरार रखती है। इसमें सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में जोड़ा गया है। राजद्रोह अब अपराध नहीं है. इसके बजाय, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों के लिए एक नया अपराध है। आतंकवाद को एक अपराध के रूप में जोड़ता है। इसे एक ऐसे कृत्य के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका उद्देश्य देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालना या लोगों में आतंक पैदा करना है। संगठित अपराध को अपराध के रूप में जोड़ा गया है। इसमें अपराध सिंडिकेट की ओर से किए गए अपहरण, जबरन वसूली और साइबर अपराध जैसे अपराध शामिल हैं। छोटे-मोटे संगठित अपराध भी अब अपराध हैं. जाति, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास जैसे कुछ पहचान चिह्नों के आधार पर पांच या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा हत्या करना एक अपराध होगा जिसके लिए आजीवन कारावास या मौत की सज़ा और जुर्माना हो सकता है।

इसमें 358 धाराएं होंगी (आईपीसी की 511 धाराओं के बजाय)

20 नए अपराध जोड़े गए हैं, 33 अपराधों में कारावास की सजा बढ़ा दी गई है, 83 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ाई गई 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सज़ा की व्यवस्था की गई है, 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का दंड पेश किया गया है। 19 धाराएं निरस्त/हटा दी गई हैं।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की जगह) नए बिल/कानून की मुख्य बातें

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करती है। सीआरपीसी गिरफ्तारी, अभियोजन और जमानत की प्रक्रिया प्रदान करता है।

सात साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच को अनिवार्य करता है। फोरेंसिक विशेषज्ञ फोरेंसिक सबूत इकट्ठा करने और प्रक्रिया को रिकॉर्ड करने के लिए अपराध स्थलों का दौरा करेंगे। सभी परीक्षण, पूछताछ और कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक मोड में आयोजित की जा सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों के उत्पादन, जिसमें डिजिटल साक्ष्य शामिल होने की संभावना है, को जांच, पूछताछ या परीक्षण के लिए अनुमति दी जाएगी। यदि कोई घोषित अपराधी मुकदमे से बचने के लिए भाग गया है और उसे गिरफ्तार करने की तत्काल कोई संभावना नहीं है, तो उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया जा सकता है और फैसला सुनाया जा सकता है। जांच या कार्यवाही के लिए नमूना हस्ताक्षर या लिखावट के साथ-साथ उंगलियों के निशान और आवाज के नमूने भी एकत्र किए जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति से नमूने लिए जा सकते हैं जिसे गिरफ्तार नहीं किया गया है।

इसमें 531 धाराएं होंगी (सीआरपीसी की 484 धाराओं के स्थान पर)

कुल 177 प्रावधान बदले गए हैं, 9 नई धाराएं, 39 नई उपधाराएं जोड़ी गई हैं और 44 नए प्रावधान और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं समयसीमा को 35 अनुभागों में जोड़ा गया है। 35 स्थानों पर ऑडियो-वीडियो प्रावधान जोड़ा गया है।

14 धाराएं निरस्त/हटा दी गई हैं

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की जगह) नए बिल/कानून की मुख्य बातें। भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (IEA) का स्थान लेता है। यह IEA के अधिकांश प्रावधानों को बरकरार रखता है जिनमें स्वीकारोक्ति, तथ्यों की प्रासंगिकता और सबूत का बोझ शामिल है। IEA दो प्रकार के साक्ष्य प्रदान करता है-दस्तावेजी और मौखिक। दस्तावेजी साक्ष्य में प्राथमिक (मूल दस्तावेज) और द्वितीयक (जो मूल की सामग्री को साबित करते हैं) शामिल हैं। भारतीय साक्ष्य विधेयक ने विशिष्टता बरकरार रखी है। यह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को दस्तावेज के रूप में वर्गीकृत करता है। IEA के तहत, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारतीय साक्ष्य विधेयक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में वर्गीकृत करता है। यह सेमीकंडक्टर मेमोरी या किसी संचार उपकरण (स्मार्टफोन, लैपटॉप) में संग्रहीत जानकारी को शामिल करने के लिए ऐसे रिकॉर्ड का विस्तार करता है। भारतीय साक्ष्य विधेयक निम्नलिखित को शामिल करने के लिए द्वितीयक साक्ष्य का विस्तार करता है (i) मौखिक और लिखित स्वीकारोक्ति, और (ii) उस व्यक्ति की गवाही जिसने दस्तावेज़ की जांच की है और दस्तावेजों की जांच में कुशल है।

इसमें 170 प्रावधान होंगे (मूल 167 प्रावधानों के बजाय) कुल 24 प्रावधान बदले गए हैं, 2 नए प्रावधान, 6 उप-प्रावधान जोड़े गए हैं 6 प्रावधान निरस्त/हटाए गए हैं।

तीन नए कानून विधेयकों का मूल्यांकन-

ताकतें-

● **आधुनिकीकरण-** विधेयक का उद्देश्य भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को प्रतिस्थापित करना है, जिन्हें पुराना और औपनिवेशिक युग के अवशेष माना जाता है। उन्हें नए, व्यापक कोड से बदलने से कानूनी प्रणाली में दक्षता, स्पष्टता और स्थिरता में संभावित सुधार हो सकता है।

● **कमियों को संबोधित करना**-प्रस्तावित बिल वर्तमान कानूनी ढांचे में कुछ मौजूदा कमियों को संबोधित करते हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) विधेयक साइबर अपराध से संबंधित अपराधों को संबोधित करने का प्रस्ताव करता है, जो स्पष्ट रूप से आईपीसी में शामिल नहीं थे।

● **समन्वय**-विधेयक का उद्देश्य विभिन्न आपराधिक कानूनों को एक छतरी के नीचे सुसंगत बनाना है, जिससे संभावित रूप से भ्रम और अस्पष्टता कम हो सके।

● **प्रक्रियात्मक सुधार**-बीएनएस विधेयक अदालती प्रक्रियाओं को सरल बनाने और मुकदमों में देरी को कम करने का प्रस्ताव करता है। इससे न्याय तक पहुंच और पीड़ित की संतुष्टि में सुधार हो सकता है।

कमजोरियाँ-

● **जल्दबाजी में मसौदा तैयार करना**-जल्दबाजी में मसौदा तैयार करने और पर्याप्त सार्वजनिक परामर्श की कमी के कारण विधेयकों की आलोचना की गई है। इससे संभावित अनपेक्षित परिणामों और चूकों के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं।

● **मौलिक अधिकारों का क्षरण**-बिल में कुछ प्रावधानों, जैसे कि पुलिस की शक्तियों में वृद्धि और कड़ी जमानत शर्तों ने मौलिक अधिकारों और उचित प्रक्रिया के संभावित क्षरण के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं।

● **स्पष्टता का अभाव**-विधेयकों में कुछ प्रावधान अस्पष्ट हैं और व्याख्या के लिए खुले हैं, जिससे आवेदन में विसंगतियां और संभावित दुरुपयोग हो सकता है।

● **दुरुपयोग की संभावना**-विस्तारित पुलिस शक्तियों और सख्त दंडों का उपयोग कुछ समूहों या व्यक्तियों को लक्षित करने के लिए किया जा सकता है, जिससे भेदभाव और शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है।

अवसर-

● **न्याय प्रणाली को मजबूत करना**-यदि प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो नए कानून भारतीय न्याय प्रणाली को आधुनिक और मजबूत कर सकते हैं, जिससे दक्षता में सुधार होगा और न्याय तक पहुंच में सुधार होगा।

● **सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना**-बिल का उपयोग कानूनी प्रणाली में मौजूदा असमानताओं और अन्याय को संबोधित करने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों के खिलाफ भेदभाव।

● **जनता का विश्वास बढ़ाना**-एक अधिक आधुनिक और कुशल कानूनी प्रणाली कानून के शासन में जनता का विश्वास बढ़ा सकती है।

● **एक मिसाल कायम करना**-इन विधेयकों का सफल कार्यान्वयन कानून के अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह के सुधारों को प्रेरित कर सकता है।

चुनौतियाँ-

● **सार्वजनिक विरोध**-विधेयकों को वकीलों, कार्यकर्ताओं और विपक्षी दलों सहित समाज के विभिन्न वर्गों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है। यह विरोध उनके सुचारू कार्यान्वयन में बाधा बन सकता है।

● **कार्यान्वयन चुनौतियाँ**-ऐसे व्यापक सुधारों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों और प्रशिक्षित कर्मियों की आवश्यकता होगी। क्षमता निर्माण और बुनियादी ढांचे का विकास महत्वपूर्ण होगा।

● **सुरक्षा और स्वतंत्रता को संतुलित करना**-विधेयकों को सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के बीच संतुलन बनाना चाहिए। यह एक नाजुक और चुनौतीपूर्ण कार्य होगा।

● **अप्रत्याशित परिणाम**-किसी भी नए कानून में अप्रत्याशित परिणाम होने की संभावना होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बिल अपने इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करें, सावधानीपूर्वक निगरानी और मूल्यांकन आवश्यक होगा। तीन नए कानून विधेयकों में भारतीय कानूनी प्रणाली को महत्वपूर्ण रूप से आधुनिक बनाने और सुधारने की क्षमता है।

हालाँकि, उनके कार्यान्वयन में संभावित कमज़ोरियों और चुनौतियों को लेकर चिंताएँ भी हैं। पूरी तरह से सार्वजनिक बहस करना और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि बिलों को इस तरह से लागू किया जाए कि उनके इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता को बरकरार रखा जा सके।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा विनिमय क्या है?

नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज या NHCX प्लेटफॉर्म आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित एक सिंगल-विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म है।

इसे भुगतानकर्ताओं (बीमाकर्ता, तृतीय-पक्ष प्रशासक, सरकारी योजना प्रशासक) और प्रदाताओं (अस्पताल, प्रयोगशालाओं, पॉलीक्लिनिक), लाभार्थियों और दावा प्रक्रिया में शामिल विभिन्न खिलाड़ियों के बीच दावों से संबंधित जानकारी के आदान-प्रदान के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में सोचें। अन्य प्रासंगिक संस्थाएँ एक ही स्थान पर।

मूल रूप से, यह एक ऐसी जगह है जहां सभी बीमाकर्ता सीधे अस्पतालों के साथ बातचीत करेंगे और तेजी से निपटान प्रक्रिया प्रदान करेंगे। तेजी से दावों के निपटान के लिए सभी प्रक्रियाओं को मानकीकृत किया जाएगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा विनिमय कैसे काम करेगा?

राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा विनिमय पोर्टल अस्पतालों और बीमा कंपनियों के बीच सूचना और दस्तावेजों के निर्बाध आदान-प्रदान के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा दावा निपटान प्रक्रिया को सरल, तेज और मानकीकृत करने के लिए तैयार है।

उद्देश्य-

1. बीमा आधार बढ़ाने के लिए बीमा पॉलिसियों में ओपीडी और फार्मेसी बिल जैसे नए प्रकार के दावे जोड़े जाने चाहिए।

2. स्वतः निर्णय, नियंत्रण धोखाधड़ी और दुरुपयोग की रोकथाम के लिए नई प्रक्रियाओं/नियमों को सक्षम करके बीमा नवाचार को सुविधाजनक बनाना।

3. परिचालन ओवरहेड्स को कम करने और पारदर्शी और नियम-आधारित तंत्र के माध्यम से भुगतानकर्ताओं और प्रदाताओं के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए दावा प्रक्रिया को मानकीकृत किया गया।

एनएचसीएक्स कैसे काम करता है?

पहले संस्करण में, NHCX कैशलेस दावों के लिए संदेश आदान-प्रदान की सुविधा पर केंद्रित है और निम्नलिखित सूचना प्रवाह के लिए विशिष्टताएँ प्रदान करता है-

1. प्रदाता/भुगतानकर्ता विवरण प्राप्त करें।

2. लाभार्थी के लिए पात्रता जांच जांच कवरेज पात्रता/पैकेज या प्रक्रिया पात्रता के लिए हो सकती है।

3. पूर्व प्रमाणीकरण अनुरोध और अनुमोदन प्रवाह - पूर्व-निर्धारण, पूर्व-प्राधिकरण के रूप में दावा प्रकार।

4. दावा अनुरोध और अनुमोदन प्रवाह-दावा प्रकार और दावा/भुगतान अधिसूचना।

5. दावों का पुनर्प्रसंस्करण-दावे की आंशिक स्वीकृति या अस्वीकृति के मामले में।

6. स्थिति जांच, नियामक अनुपालन आदि के लिए दावा डेटा खोजें/लाएं।

यह आपकी दावा प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करेगा?

वर्तमान में दावा दायर करने की प्रक्रिया-

1. अब कैशलेस दावों के लिए आवेदन करते समय पॉलिसीधारक को संबंधित फॉर्म और दस्तावेजों के साथ अस्पताल में एक स्वास्थ्य बीमा कार्ड जमा करना होगा।

2. फिर अस्पताल मैन्युअल रूप से दावा प्रपत्र भरते हैं, दस्तावेज स्कैन करते हैं, और इन्हें बीमा कंपनियों या तीसरे पक्ष प्रशासकों के कई पोर्टलों पर अपलोड करते हैं।

3. बीमाकर्ता की ओर से, डेटा को डिजिटल किया जाता है, मैन्युअल रूप से प्रमाणित किया जाता है और निर्णय लिया जाता है। फिर बीमाकर्ता या टीपीए बीमाधारक की छुट्टी की प्रक्रिया के लिए दस्तावेजों को वापस अस्पताल भेजता है।

एनएचसीएक्स की शुरूआत के साथ-

अधिकांश प्रक्रियाएं डिजिटलीकृत और स्वचालित होंगी।

1. एक सामान्य दावा प्रारूप होगा जिसका उपयोग सरकारी या निजी स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और एनएचए द्वारा परिभाषित अस्पतालों में किया जाएगा।

2. अस्पताल बीमाकर्ता के आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (एबीएचए) नंबर के माध्यम से उसके डिजिटल विवरण तक पहुंच सकते हैं।

3. एनएचसीएक्स पोर्टल निर्दिष्ट बीमाकर्ता को भेजने से पहले विवरणों को स्वचालित रूप से सत्यापित करेगा।

4. बीमाकर्ता इसे डिजिटल रूप से सत्यापित करेगा और निर्णय देगा, और अस्पताल डिस्चार्ज की प्रक्रिया करेगा।

स्वास्थ्य बीमा पॉलिसीधारकों के लिए, NHCX प्लेटफॉर्म दावा निपटान प्रक्रिया को तेज़ करेगा जिससे अस्पताल से छुट्टी मिलने का प्रतीक्षा समय कम हो जाएगा।

इससे बीमा कंपनी द्वारा संसाधित प्रत्येक दावे के लिए दावा प्रसंस्करण लागत कम होने की भी उम्मीद होगी, जिससे बीमाकर्ता की परिचालन लागत में कमी आएगी।

नीति आयोग @ ई-फास्ट इंडिया पहल में NITI गियरशिफ्ट चैलेंज

नीति आयोग ने IIM बैंगलोर के सहयोग से e-First India पहल के हिस्से के रूप में NITI गियरशिफ्ट चैलेंज शुरू करने की घोषणा की।

इस अग्रणी हैकथॉन का उद्देश्य देश की गंभीर आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करते हुए भारत में शून्य-उत्सर्जन ट्रकों (ZERO Emission Trucks) को अपनाने के लिए नवीन व्यवसाय मॉडल को बढ़ावा देना है।

NITI गियरशिफ्ट चैलेंज छात्रों, परिवहन सेवा व्यवसायियों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं को नवीन व्यवसाय मॉडल विकसित करने के लिए आमंत्रित करता है जो इलेक्ट्रिक ट्रकों को अपनाने में वित्तीय, तकनीकी और परिचालन चुनौतियों का समाधान करते हैं। कार्यक्रम ने ई-फास्ट इंडिया ज्ञान भागीदारों, वित्तीय संस्थानों और उद्योग मंचों से भागीदारी प्राप्त की है।

भारत का माल ढुलाई क्षेत्र अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, जो 1.4 अरब से अधिक लोगों तक माल की सुचारू डिलीवरी सुनिश्चित करता है। भारत की वार्षिक डीजल खपत में सड़क माल ढुलाई का योगदान 55 प्रति. और सड़क परिवहन से लगभग 40% COw उत्सर्जन है, इसलिए अधिक टिकाऊ समाधानों की ओर संक्रमण की तत्काल आवश्यकता है। माल परिवहन का विद्युतीकरण एक प्रमुख प्राथमिकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रक उत्सर्जन को कम करने, वायु गुणवत्ता में सुधार और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक परिवर्तनकारी अवसर प्रदान करते हैं।

गियरशिफ्ट चैलेंज भारत में टिकाऊ माल परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रतिभागियों की रचनात्मकता और विशेषज्ञता का उपयोग करके, हैकथॉन का लक्ष्य व्यावहारिक समाधान उत्पन्न करना है जो शून्य-उत्सर्जन ट्रकों को अपनाने में तेजी लाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों को लाभ होगा।

महाकाल सवारी मार्ग की व्यवस्था समय पूर्व सुनिश्चित करें-आयुक्त आशीष पाठक

उज्जैन। श्रावण एवं भादौ मास में निकलने वाली भगवान श्री महाकालेश्वर की सवारी के दौरान की जाने वाली निगम से सम्बंधित समस्त आवश्यक व्यवस्थाओं को समय पूर्व किया जाना सुनिश्चित करें। यह निर्देश आयुक्त श्री आशीष पाठक द्वारा ग्राण्ड होटल पर आयोजित आवश्यक बैठक में दिए गए। आपने कहा कि दिनांक 22 जुलाई 2024 से भगवान श्री महाकालेश्वर की सवारी निकाली जावेगी जो शहर के विभिन्न मार्गो से होते हुए पुनः मंदिर पहुंचेगी, सवारी के दौरान बड़ी संख्या में श्रृद्धालुओं दर्शन हेतु उपस्थित रहेंगे श्रृद्धालाओं की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए निगम से सम्बंधित समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं समय पूर्व सुनिश्चित की जाए। आपने सम्बंधित अधिकारियों विशेषकर झोनल अधिकारियों, अतिक्रमण गैंग प्रभारी एवं सफाई अमले को निर्देशित किया कि सम्पूर्ण सवारी मार्ग पर कहीं भी नाली अथवा नाला खुला हुआ ना हो, सवारी मार्ग में आने वाले ऐसे भवन जो जर्जर एवं गिराउ अवस्था में है उन्हें चिन्हित किया जाकर सूचना बोर्ड लगाए जाएं, सवारी मार्ग पर आवश्यक संधारण एवं पेंचवर्क कार्य समय पूर्व सुनिश्चित किये जाए, सवारी मार्ग से अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही प्राथमिकता के साथ की जाए, मार्ग में फायर ब्रिगेड की व्यवस्था हो, पथ प्रकाश व्यवस्था का विशेष ध्यान दिया जाए, पेयजल व्यवस्था अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर पानी के टेंकर खडे किये जाए, मार्ग संकेतक लगाए जाए, घाटों पर नदी में पानी गहरा है सम्बंधित सूचना बोर्ड लगवाए जाए साथ ही समस्त व्यवस्थाएं सेक्टरवार निर्धारित की जाकर समय पूर्व की जाना सुनिश्चित करें।

आपने मोहर्रम पर्व पर की जाने वाली व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाकर निकास चौराहे, गीता कॉलोनी क्षैत्र, केडीगेट पर साफ सफाई, पथ प्रकाश व्यवस्था समय पूर्व सुनिश्चित की जाए।

बैठक में अपर आयुक्त श्री आर.एस. मण्डलोई, उपायुक्त श्री संजेश गुप्ता, श्री प्रेम कुमार सुमन, श्री मनोज मौर्य, श्रीमती आरती खेडेकर, सहायक आयुक्त श्री प्रदीप सेन, कार्यपालन यंत्री श्री पीयुष भार्गव, श्री जगदीश मालवीय, झोनल अधिकारी श्री डीएस परिहार, श्री साहिल मैदावाल, श्री राजकुमार राठौर, श्री दीपक शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

सात फेरे के बाद चिन्तामन गणेश मन्दिर में किया पौधारोपण

उज्जैन। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की प्रेरणा से प्रदेश में 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान जन-आन्दोलन बन गया है। उज्जैन में चारों ओर व्यापक स्तर पर पौधारोपण किया जा रहा है। समाज के हर वर्ग, हर आयु का व्यक्ति इस अभियान से जुड़ गया है।

इसी अनुक्रम में अभियान से प्रेरित होकर राजस्थान के नव-विवाहित जोड़े श्री विशाल दर्जी-श्रीमती यशिका खत्री ने चिन्तामन गणेश मन्दिर में अपने विवाह के सुअवसर को यादगार बनाते हुए सात फेरों के तुरन्त बाद अशोक के पौधों का रोपण किया।

इसके साथ ही उन्होंने पौधों के संरक्षण का संकल्प भी लिया। इसी क्रम में चिन्तामन गणेश मन्दिर प्रशासक श्री अभिषेक शर्मा ने भी मंदिर परिसर में अशोक का पौधा रोपकर पौधों के संरक्षण का संकल्प लिया और वायुदूत अंकुर एप डाउनलोड कर पौधरोपण की फोटो भी अपलोड की।

इस अवसर पर पुजारी गणेश गुरु, श्री पलाश राय, श्री बने सिंह उपस्थित रहे।

नवविवाहित दम्पत्ति ने बताया कि आज हम अपने विवाह के लिये राजस्थान से चिन्तामन गणेश मन्दिर आये थे। हमें लगातार 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान की जानकारी प्राप्त हो रही थी कि सभी अपनी मां के नाम एक पौधे का रोपण कर रहे हैं। इसी से प्रेरणा लेकर हमने भी नव-विवाहित जीवन में प्रवेश करने से पहले पौधारोपण किया और प्रकृति के संरक्षण का संकल्प लिया।

एएसआई ने हाईकोर्ट में पेश की दो हजार पन्नों की भोजशाला की सर्वे रिपोर्ट

इंदौर। मध्य प्रदेश के धार जिला मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक भोजशाला मामले में लगातार 98 दिन तक चले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के सर्वे की रिपोर्ट मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में प्रस्तुत की गई है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के वकील हिमांशु जोशी ने सोमवार को रिपोर्ट इंदौर हाई कोर्ट में पेश की। यह रिपोर्ट मीडिया से शेयर नहीं करने के निर्देश सभी पक्षों को दिए गए हैं। पता चला है कि यह रिपोर्ट 2000 से ज्यादा पन्नों में है। सर्वे और खुदाई के दौरान मिले 1700 से ज्यादा प्रमाण-अवशेष इस रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं। इस पर आगामी 22 जुलाई को सुनवाई होगी।

एएसआई के वकील हिमांशु जोशी ने बताया कि अत्याधुनिक तकनीक से की गई विज्ञानी सर्वे की रिपोर्ट पेश कर दी है। उनका कहना है कि रिपोर्ट दो हजार पेज की है। इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकते। इस रिपोर्ट में 98 दिन चले सर्वे में एकत्रित किए 1700 से ज्यादा प्रमाण और खुदाई में मिले अवशेषों का विश्लेषण शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट की एक-एक प्रति मामले से जुड़े सभी पक्षकारों को उपलब्ध करवाई गई है। इसके बावजूद रिपोर्ट में क्या है, यह अब तक रहस्य बना हुआ है। इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद ही पता चलेगा कि धार भोजशाला मंदिर है या मस्जिद।

इधर, हिंदू पक्ष के लोग दावा कर रहे हैं कि जो सर्वे रिपोर्ट पेश हुई है, उससे साफ हो जाएगा कि इसे राजा भोज ने बनाया था। हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने दावा किया कि जो सर्वे हमारे सामने हुआ था, उस आधार पर हम कह रहे हैं कि यह इमारत राजा भोज के काल की ही साबित होगी, जिसे वर्ष 1034 में बनाया गया था। एएसआई को इस सर्वे में कई प्राचीन मूर्तियां मिली हैं, जो परमारकालीन हो सकती हैं। इस तरह ये परमारकालीन इमारत है। उन्होंने कहा कि सर्वे के दौरान सामने आए अवशेषों से लगभग तय माना जा रहा है कि यह परमारकालीन यानी 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच का निर्माण है। इस बीच, गर्भगृह के पास 27 फीट लंबी दीवार भी मिली है, जो ईंटों से बनी है। पुरातत्वविदों का मानना है कि ईंटों से निर्माण और भी प्राचीन समय में होता था। मोहन जोदड़ो सभ्यता के समय, यानी यह स्थान और भी प्राचीन हो सकता है। गौरतलब है कि भोजशाला को लेकर दशकों से विवाद चल रहा है। हिंदू फॉर जस्टिस ने एक वर्ष पहले मप्र उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के समक्ष एक याचिका दायर कर भोजशाला परिसर में शुक्रवार को होने वाली नमाज रोकने की गुहार लगाई थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि हिंदू लोग मंगलवार को भोजशाला में पूजा करते हैं और मुस्लिम लोग शुक्रवार को वहां नमाज कर उसे अपवित्र कर देते हैं। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान 11 मार्च 2024 को आदेश दिया था कि एएसआई भोजशाला का विज्ञानी सर्वे कर रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करे। यह सर्वे 98 दिन चला। जिला प्रशासन की वेबसाइट के अनुसार भोजशाला राजा भोज ने बनवाई थी। यह यूनिवर्सिटी थी, जिसमें वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। मुस्लिम शासक ने इसे मस्जिद में परिवर्तित कर दिया था। इसके अवशेष प्रसिद्ध मौलाना कमालुद्दीन मस्जिद में देखे जा सकते हैं। यह भोजशाला के कैंपस में स्थित है जबकि देवी की प्रतिमा लंदन के म्यूजियम में रखी है। साल 2006, 2012 और 2016 में शुक्रवार को वसंत पंचमी आई तो विवाद की स्थिति बनी। वसंत पंचमी पर हिंदू पक्ष को पूजा जबकि शुक्रवार होने से मुस्लिमों को नमाज की अनुमति भी है। ऐसे में वसंत पंचमी शुक्रवार को आने पर समझौते के बीच पूजा और नमाज दोनों करवाए जाते हैं।

स्वताधिकारी/प्रकाशक मनमोहन शर्मा के लिये साप्ताहिक उज्जैन टाइम्स 110, तिरुपति एवेन्यू, होटल नक्षत्र के पीछे, पंचक्रोशी मार्ग, उज्जैन (म.प्र.) से प्रकाशित एवं ज्योति ट्रेडर्स एवं प्रिन्टर्स न्यू रोड़, उज्जैन से मुद्रित।

● प्रधान सम्पादक : मनमोहन शर्मा मोबा. 9827233734 manmohan680@gmail.com (सभी वाद-विवादों का न्याय क्षेत्र उज्जैन रहेगा)। (म.प्र. शासन से 01-04-1997 से समाचार पत्र विज्ञापनों हेतु अनुमोदित)